



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2004/वैशाख 27, 1926

No. 107]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2004/VAISAKHA 27, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच समाप्ति की अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2004

**विषय:-** जापान के मूल के अथवा वहाँ से आयातित मेटालर्जिकल कोक के आयातों से सम्बन्धित पाटनरोधी जाँच ।

सं. 14/41/2002-डीजीएडी.— 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत जापान से मेटालर्जिकल कोक के आरोपित पाटित आयातों की जाँच 20 मार्च, 2003 की अधिसूचना के तहत शुरू की थी । यह जाँच जापान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मेटालर्जिकल कोक (मेटकोक, जिसे आगे सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से इण्डियन मेटलर्जिकल कोक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमसीओएमए), (जिसे आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) से प्राप्त लिखित आवेदन के आधार पर शुरू की गयी थी ।

2. प्राधिकारी ने जापान (जिसे आगे सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के सीमाशुल्क कोड 27.04 और आईटीसी एचएस वर्गीकरण नियम, 2704.00 के अंतर्गत वर्गीकृत मेटलर्जिकल कोक के आयातों के बारे में पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए 20 मार्च को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी ।

3. जापान के निम्नलिखित निर्यातों/उत्पादकों द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर/उससे सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत की गयी थी :-

1. मै0 मित्सुबिशी कार्पोरेशन, जापान
2. मै0 जेएफई स्टील कार्पोरेशन, जापान

4. प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर/उससे सम्बन्धित सूचना सम्बद्ध वस्तु के अनेक आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा भी प्रस्तुत की गयी थी जिनके विचारों पर जाँच के विभिन्न चरणों में गौर किया गया था ।

5. पाटन, क्षति और सम्बद्ध देश से पाटित आयातों एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की प्रारम्भिक जाँच पूरी करने के बाद प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में 14 अक्टूबर, 2003 को प्रकाशित अधिसूचना के तहत अपने प्रारम्भिक जाँच परिणाम अधिसूचित किए थे जिसमें संदर्भ कीमत के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गयी थी । प्राधिकारी द्वारा कम शुल्क के सिद्धांत के आधार पर संस्तुत संदर्भ कीमत 118.44 अमरीकी डॉलर प्रति मी0 टन निर्धारित की गयी थी ।

6. प्राधिकारी ने पाटन, क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की आगे और जाँच की तथा सार्वजनिक सुनवाई की, घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशी निर्यातकों के आंकड़ों का सत्यापन भी किया । आपवादिक परिस्थितियों के कारण केन्द्र सरकार ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(1) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जाँच को पूरा करने की समयावधि 20 सितम्बर, 2004 तक बढ़ा दी थी ।

7. याचिकाकर्ताओं ने जापान से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के अपने अनुरोध को वापस लेते हुए 12 मई, 2004 के अपने पत्र के तहत प्राधिकारी के समक्ष लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया है । अपने लिखित अनुरोध में याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निवेदन किया है :-

♦ कि भारत के जिम्मेवार निगमित नागरिक के रूप में याचिकाकर्ता प्राधिकारी की जानकारी में जाँच अवधि के बाद की अवधि में मेटकोक बाजार में अत्यधिक बढ़ती हुई परिस्थितियों को लाना चाहते हैं । विश्व में मेटलर्जिकल कोक और कोक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (विश्व बाजार में जिसका हिस्सा लगभग 90% है) होने के कारण चीन ने अपनी घरेलू माँग की वजह से विश्व बाजार में अपनी आपूर्तियों पर अंकुश लगा दिया है! इसके परिणामस्वरूप जापान की प्रचलित कीमत (यदि सामग्री उपलब्ध है) एफओबी आधार पर 300 अमरीकी डॉलर से अधिक हो गयी है । तथापि, याचिकाकर्ताओं की राय में याचिकाकर्ता के अनुरोध को वापस लिए जाने के बावजूद इससे जाँच अवधि के दौरान चीन और जापान द्वारा पाटित की गयी मात्रा का संकेत मिलता है ।

♦ कि जापान के पास मेटलर्जिकल कोक का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है और वह अपने आपूर्तिकर्ताओं और भारत में विद्यमान कीमत के बीच कीमत अंतर को संतुलित करके भारत में उत्पाद (मेटकोक) का पाटन कर रहा था ।

- ◆ कि कोयले का अपना कोई स्रोत न होने के कारण जापान निकट भविष्य में भारत में पाटन जारी रखने में असमर्थ है।
- ◆ कि याचिकाकर्ताओं को इस बात की पूरी जानकारी है कि भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र में यह सुस्थापित कानून है कि जाँच अवधि से संबंधित आंकड़े ही किसी पाटनरोधी जाँच में प्रासंगिक होते हैं और जाँच अवधि के बाद हुए घटनाक्रमों का मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, जिम्मेवार निगमित नागरिक के रूप में वे सरकार से उस शुल्क को लगाने की अपेक्षा नहीं करते हैं जो आज की स्थिति में प्रभावहीन हो गया है।
- ◆ कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के अनुरोध को वापस लिया जाना याचिका में दिए गए उनके तर्कों तथा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर जापान के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए प्राधिकारी से सम्पर्क करने के उनके भावी अधिकारों के प्रति भेदभाव रहित है।

8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी कोई सार्वजनिक सूचना जारी करके उस स्थिति में किसी जाँच को तुरंत समाप्त कर देगा यदि उसे प्रभावित हुए घरेलू उद्योग से अथवा उसकी ओर से, जिसके कहने पर उक्त जाँच शुरू की गयी थी, ऐसा करने के लिए लिखित में कोई अनुरोध प्राप्त होता है।

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरोपित पाटन और क्षति की जाँच अपने सदस्यों की ओर से इण्डियन मेटलर्जिकल कोक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमसीओएम) द्वारा दायर पूर्णतः प्रलेखित लिखित अनुरोध के आधार पर शुरू की गयी थी। उन्हीं आवेदकों ने बाजार में बदली हुई स्थिति तथा शामिल उत्पाद की कीमत संरचना, जिसके निकट भविष्य में परिवर्तित होने की संभावना नहीं है, को ध्यान में रखते हुए शुल्क लगाने के अपने मूल अनुरोध को वापस लेते हुए अब लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के अनुरोध को वापस लिया जाना याचिका में दिए गए उनके तर्कों तथा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर जापान के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए प्राधिकारी से सम्पर्क करने के उनके भावी अधिकारों के प्रति भेदभाव रहित है।

10. अतः ऊपर उल्लिखित पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) के अनुसार प्राधिकारी 20 मार्च, 2003 की अधिसूचना के तहत शुरू की गयी जाँच और इस मामले से संबंधित समस्त कार्रवाइयों को एतद्वारा समाप्त करते हैं।

11. प्राधिकारी 14 अक्टूबर की अधिसूचना के तहत अधिसूचित अपने प्रारम्भिक जाँच परिणामों द्वारा संस्तुत और राजस्व विभाग द्वारा 13 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना सं० 167/2003-सीशु के तहत लगाए गए अनंतिम उपाय को वापस लेने की सिफारिश भी करते हैं।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****TERMINATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2004

**Sub: Anti-Dumping Investigation concerning imports of Metallurgical Coke originating in or imported from Japan**

No. 14/41/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, the Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, initiated an investigation vide notification dated 20<sup>th</sup> March 2003, into the alleged dumped imports of metallurgical coke from Japan. The investigation was initiated on the basis of a written application received from Indian Metallurgical Coke Manufacturer's Association (IMCOMA), (hereinafter referred to as petitioner) on behalf of domestic industry, alleging dumping of Metallurgical Coke (Metcoke, hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Japan.

2. The Authority issued a public notice dated 20<sup>th</sup> March, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of Metallurgical Coke classified under custom Code 27.04 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 and under ITC HS Classification Rule 2704.00, originating in or exported from Japan (hereinafter referred to as subject country).

3. Response/information to the questionnaire/notification was filed by the following exporters/producers from Japan:-

- I. M/s Mitsubishi Corporation, Japan
- II. M/s JFE Steel Corporation, Japan

4. Response/information to the questionnaire/notification was also filed by a number of Importers and users of the subject goods whose views were taken into account at various stages of the investigation.

5. After completion of preliminary investigation into dumping, injury and causal link between the dumped imports from the subject country and injury

suffered by the domestic industry, the authority notified its preliminary findings, vide notification dated 14<sup>th</sup> October 2003, published in the Gazette of India Extraordinary, recommending imposition of antidumping duty on reference price basis. The reference price recommended by the authority on the basis of lesser duty principles was fixed at US\$118.44 Per MT.

6. The Authority conducted further investigation into the dumping, injury, and causal link between dumping and injury and also conducted public hearing, verification of domestic industry, as well as, foreign exporter's data. Due to exceptional circumstance, the Central Government, in terms of the powers conferred upon it under Rule 17 (1) of the Antidumping Rules, extended the time period for completion of the investigation till 20<sup>th</sup> September 2004.

7. The petitioners vide their letter dated 12<sup>th</sup> May 2004 have made a written submission before the Authority withdrawing their request for imposition of the antidumping duty on imports of the subject goods from Japan. In their written submission the petitioners have inter-alia submitted:

- ◆ That as responsible corporate citizens of India the petitioners wish to bring to the notice of the authority the drastic changed circumstances in Metcoke market in the post POI period. China being the largest supplier of metallurgical coal and coke globally (dominating about 90% of global trade) has clamped up its supplies in the global market due its own domestic demand. As a result of which the prevailing price from Japan (if material is available) is far in excess of US\$300 on FOB basis. This however, in the opinion of the petitioners, highlights the extent of dumping resorted to by China and Japan during the POI, notwithstanding their request for withdrawal of the petition.
- ◆ That Japan has no known source of metallurgical coal and was dumping the product (Metcoke) in India by leveraging the price differential between its suppliers and prevailing price in India.
- ◆ That Japan with no coal resources of its own is unable to continue to dump into India in the short run.
- ◆ That the petitioners are fully aware that it is settled law in India and in intentional jurisprudence that data pertaining to the POI alone is relevant in an AD investigation and post POI developments have no bearing on the case. However, as responsible corporate citizens they do not want the Government to put in place a levy, which in today's term will have no impact.
- ◆ That their withdrawal of the request for imposition of Antidumping Duty is without prejudice to their contentions raised in the petition and their

future rights to approach the Authority for imposition of Antidumping Duty against Japan if the situation so arises.

8. Rule 14 (a) of the Antidumping Rules provide that the Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately, if it receives a request in writing for doing so, from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.
9. The Authority notes that the investigation into alleged dumping and injury was initiated on the basis of fully documented written request filed by the Indian Metallurgical Coke Manufactures Association (IMCOM) on behalf of its members. The same applicants have now made a written submission withdrawing their original request for imposition of the duty in view of the changed condition in the market and the price structure of the product involved, which is unlikely to change in the short run. The Authority also notes the contention of the petitioners that the withdrawal of their petition is without prejudice to their contentions raised in the petition and their future rights to approach the Authority for imposition of Antidumping duty against Japan, if the situation so arises.
10. Therefore, in terms of Rule 14 (a) of the Antidumping Rules referred above, the Authority hereby terminates the investigation initiated vide notification dated 20<sup>th</sup> March 2003 and all proceedings connected with this case.
11. The Authority also recommends withdrawal of the provisional measure recommended vide its Preliminary Findings notified vide notification dated 14<sup>th</sup> October 2003 and imposed by the Department of revenue, vide notification No. 167/2003-Cus. Dated 13<sup>th</sup> November 2003.

ABHIJIT SENGUPTA, Addl. Secy. & Designated Authority